सितंबर, 2018

आपदा संवाद

AAPDA SAMVAAD

केरल की बाढ़

KERALA FLOODS

गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का दौरा

गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने 1 अगस्त, 2018 को गाजियाबाद में एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन का निरीक्षण किया।

यूनिट ने एक प्रस्तुति दी और शहरी खोज तथा बचाव प्रचालन के उन्नत उपकरणों को प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, प्रचालन का एक सजीव प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने बटालियन के नए निर्मित क्षेत्र को भी देखा।

किरेन रीजीजू ने नगालैंड की बाढ़ स्थिति की समीक्षा की

माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रीजीजू ने 05 अगस्त, 2018 को नगालैंड में दीमापुर तथा कोहिमा जिलों के बाढ़ तथा/अथवा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का, स्थिति और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा करने के लिए, दौरा किया।

दौरा करते समय, श्री रीजीजू के साथ एनडीएमए, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा एनडीआरएफ के अधिकारियों की टीम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीफ्यू राव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।

टीम ने स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया और उसके बाद एक समीक्षा बैठक आयोजित की।

श्री रीजीजू ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को सभी संभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगी।

केरल के लिए राहत प्रयास

एनडीएमए ने राज्य के राहत प्रयासों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए, गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ)/सिविल सोसाइटी संगठनों (सीएसओ) के बीच समन्वय को सुकर बनाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया है।

श्री पुनीत कुमार, रेजिजेंट कमिश्नर, केरल सरकार ने राहत सामग्री की वास्तविक जरूरतों पर भागीदारों पर ब्रीफ किया। उन्होंने उन प्रभावित लोगों तक पहुंचने की जरूरत पर भी बल दिया जो राहत शिविरों में नहीं थे।

हर किसी से एक टीम में रूप में काम करने के लिए आग्रह करते हुए, एनडीएमए ने कहा ही एनजीओ पुनर्बहाली, पुनर्निर्माण तथा पीढ़ितों को मनो–सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे।

बाद में, एनडीएमए से विशेषज्ञ की एक टीम ने स्थिति का आंकलन करने तथा सिफारिशें करने के लिए राज्य का भी दौरा किया। एनडीएमए ने भूस्खलन प्रबंधन पर विशेषज्ञों की एक टीम का भी गठन किया जिसने राज्य में बड़े भूस्खलन स्थलों का दौरा किया, संभव कारणों की जांच की और उपचारी उपायों का सुझाव दिया।

चार नई एनडीआरएफ बटालियनें

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 09 अगस्त, 2018 को देश के आपदा मोचन सेटअप को और मजबूती प्रदान करने के लिए चार नई बटालियनों को स्थापित करने के कार्य को मंजूरी दी। देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए, इससे मोचन समय को कम करने में सहायता मिलेगी।

प्रारंभ में दो बटालियनों की भारत–तिब्बत सीमा पुलिस में तथा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) तथा असम राइफल्स, प्रत्येक में एक–एक बटालियन की स्थापना की जाएगी। बाद में इनको एनडीआरएफ बटालियन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा और इनको जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।

एनडीआरएफ एक विशिष्ट बल है जिसकी स्थापना आपदाओं अथवा अन्य खतरनाक परिस्थितियों के दौरान राहत तथा बचाव के विशेष कार्यों के लिए वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इस बल की 12 बटालियनें हैं जिसमें से प्रत्येक में 1000 से अधिक कार्मिक हैं।

इस बल ने अब तक पूरे देश में 3000 से अधिक अभियान चलाए हैं। इसने वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप में भी सराहनीह भूमिका निभाई है। इस वर्ष केरल की बाढ़ में इसके बहादुरी भरे कारनामों की बड़े पैमाने पर तारीफ की गई।

आंधी–तूफान और लू जोखिम न्यूनीकरण पर बैठकें

एनडीएमए ने 27 अगस्त, 2018 को लू न्यूनीकरण पर अब तक की गई प्रगति के काम की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति की एक बैठक आयोजित की। विशेषज्ञ समिति ने लू की रोकथाम तथा प्रबंधन पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश–2017 की समीक्षा की और उन उभरते मुद्दों पर चर्चा की जिनका लू जोखिमों को कम करने के लिए समाधान करना आवश्यक है। लू तथा आंधी–तूफान से कुछ सर्वाधिक शहरों में किए जा रहे संकेंद्रित प्रयासों पर रिपोर्टिंग को और बेहतर बनाने पर चर्चा की गई ताकि राज्यों को इन आपदाओं का सामना करने में मदद मिले।

भारत मौसम विज्ञान विभाग, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम–राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (आईडीएसपी–एनसीडीसी), बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय संसाधन रक्षा परिषद (एनआरडीसी), भारतीय जन स्वास्थ्य

संस्थान (आईआईपीएच) और विश्वेसरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

प्राधिकरण ने 23 अगस्त, 2018 को आंधी–तूफान, बिजली कड़कने, प्रचंड हवाओं तथा तेज हवाओं पर एनडीएमए दिशानिर्देश को तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समूह की एक बैठक का भी आयोजन किया गया।

भूस्खलन जोखिम प्रशमन पर प्रशिक्षण

एनडीएमए ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान–मंडी के सहयोग से 27 अगस्त से 31 अगस्त, 2018 तक 'भूस्खलन प्रशमन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने' के विषय पर एक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। आईआईटी–मंडी में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की जान–माल पर भूस्खलन के असर को कम करने के लिए बेहतर भूस्खलन प्रशमन तथा डीपीआर तैयार करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षित करना था।

समापन सत्र के दौरान बोलते हुए ले. जनरल एन.सी. मरवाह (सेवानिवृत्त) सदस्य, एनडीएमए ने भूस्खलन से निपटने की तैयारी तथा प्रशमन पर फोकस करने की आवश्यता को रेखांकित किया। उन्होंने हमारे दुगर्म्य भूभाग के क्षेत्रों की समस्या के समाधान करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कम लागत वाले समाधान को उपलब्ध कराने के लिए देशीय अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर भी बल दिया।

कार्यक्रम ने प्रमुख समुहों जिनमें भू–तकनीकी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, भू–विज्ञानी, आपदा प्रबंधक आदि शामिल थे, को एक जगह इकट्ठा किया जो अपने संबंधित राज्यों में प्रशमन उपायों को विकसित, अपनाने, लागू करने तथा प्रवृत्त करने की दिशा में काम करेंगे। •

केरल की बाढ़

एक असाधारण मॉनसूनी मौसम, बेतहाशा बारिश, भूस्खलन, बिल्डिंगों का ढहना, पेड़ों का गिरना, बाधित संचार,...

बाढ़ ग्रस्त केरल जिसने 100 वर्षों में एक बार घटित होने वाली अति–भयंकर स्थिति का सामना किया।

54 लाख से ज्यादा लोग राज्य के सभी जिलों में प्रभावित हुए मुख्यमंत्री श्री पिनराई विजयन ने स्थिति का प्रत्याशित स्थित के रूप में वर्णन किया। समय बर्बाद करने का यह मौका नहीं था। जहां राज्य मशीनरी आपदा के असर को समाप्त करने के लिए दिन रात काम कर रही थी, वहीं केंद्र ने भी केरल के लोगों को राहत देने के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी।

शसस्त्र बलों, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, केंद्रीय शसस्त्र पुलिस बल, तट रक्षक और केंद्र सरकार के हितधारक मंत्रालयों तथा विभागों ने राहत तथा बचाव अभियानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंधे–से–कंधा मिलाकार काम किया। 2,80,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 14 लाख से अधिक लोगों को 5,600 राहत शिविरों में लाया गया। खाने के पैकेटों, कपड़ों, बिस्तर की चादरों, कंबलों, मोमबत्तियों, माचिसों, मच्छर भगाने की मशीनों, क्लोरीन की गोलियों आदि जैसी जरूरी चीजों को बांटा गया। चिकित्सा शिविरों को स्थापित किया गया; अनिवार्य दवाइयों को उपलब्ध कराया गया।

18 अगस्त, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ स्थिति का हवाई दौरा किया, लोगों की आपदा से लड़ने के जज्बे की तारीफ की और उनको केंद्र से लगातार सहायता दिलाने का वादा किया। उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए बाढ़ ग्रस्त पुल में जाने वाले एनडीआरएफ कार्मिकों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।

प्रभावित केरल में हताश तथा तबाही के वीडियो के बीच में, एक वीडियो ऐसा भी जारी किया गया जिसमें एनडीआरएफ के कुछ जवान एक पानी भरे पुल पर से दौढ़ रहे हैं और उसने बाजुओं में एक बच्चा को उन्होंने पकड़ा हुआ है जबकि पुल पर बाढ़ का पानी पूरी तरह भर गया था और एनडीआरएफ के कुछ जवान बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के लिए आशा की एक किरण साबित हुए।

बच्चा तेज बुखार से तप रहा था और उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। कनहैया कुमार जिनकी बचाव तथा राहत अभियानों में इड्डुक्की जिले में तैनाती की गई थी, ने कहा मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है और मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अपने काम के लिए इतनी तारीफ मिलेगी। उसने आगे कहा कि मैं लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहुंगा कि उन्होंने मेरे इस काम के लिए मुझे प्यार तथा सम्मान दिया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्य द्वारा दी गई 100 करोड़ रुपए की सहायता के अलावा केंद्र की तरफ से 500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की। यह अग्रिम सहायता है और केंद्र प्रक्रिया अनुसार नुकसानों का आंकलन पूरा हो जाने के बाद अतिरिक्त फंड जारी करेगा।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने आपदा में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति और जिनको गंभीर चोटें आई हैं उन्हें 50 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की अनुग्रह राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की भी घोषणा की।

पूर्व में, केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री में बाढ़ की समीक्षा करने के लिए केरल का दौरा किया। एक अंतर–मंत्रालयीन केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) में भी नुकसानों का आंकलन करने के लिए 7–12 अगस्त के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया।

इसी दौरान, प्रधानमंत्री के निर्देशों पर राष्ट्रीय संकटकाल प्रबंधन समिति ने नियमित बैठकें की जिनकी शुरूआत 16 अगस्त, 2018 से हुई और इनमें स्थिति, तैयारी, बचाव तथा राहत अभियानों का जायजा लिया गया और यह निर्देश दिए गए की इस संकट से निपटने के लिए केरल को तुंरत और लगातार सहायता प्रदान की जाए।

इसके अलावा, केंद्र ने विभिन्न उपायों जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मकानों का निर्माण; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण

गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर द्वारा सुरक्षित निकाला गया।

एक गर्भवती महिला जो अल्पुजा जिले में अपने घर की छत पर बाढ़ के दौरान फस गई थी, को भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक हेलीकॉप्टर की मदद से बाहर निकाला गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसने एक बालक को जम्न दिया।

एक परिवार, जिसक घर में पहले की काफी पानी घुस चुका था, द्वारा महिला की मदद के लिए फोन द्वारा गुहार लगाए जाने पर नेवी ने महिला को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर रवाना किया। पहले एक डॉक्टर को स्थिति का जायजा लेने के लिए नीचे उतारा गया। उसके बाद महिला को हेलीकॉप्टर की मदद से घर से सुरक्षित रूप से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। भारतीय नौसेना ने सोशल नेटवर्किंग साइट टिव्टर पर एक वीडियो डाला तथा लिखा 'एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर की सहायता से संजीवनी अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर को मकान की छत पर पहले नीचे उतारा गया ताकि वह महिला की स्थिति का जायजा ले सके और बाद में उसको सुरक्षित बचाने का अभियान सफल रहा' इसको दोबारा ट्वीट किया गया ताकि लोगों के बीच इस अच्छी खबर को सांझा किया गया।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम और राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई, एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को राजमार्ग विद्युत व्यवस्था के पुनरुद्धार के आदि के काम में राज्य की मदद करते हुए अतिरिक्त 5.5 करोड़ श्रमिक दिवसों जैसे अनेक उपयों की घोषणा की है।

विभिन्न राज्य सरकारें केरल को मदद भरा हाथ बढ़ाने के लिए भी आगे आईं।

जैसे ही बारिश रुकी और पानी का स्तर घटना शुरू हुआ, राज्य में बाढ़ प्रभावित इलाकों में संक्रामक रोग फैल गए। राज्य में परिस्थित के जरूरतों को देखते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए मानदंडों को शिथिल किया ताकि सभी जरूरी सहायता तथा समर्थन–डॉक्टर, जन–चिकित्सा टीमें जिनमें जन–चिकित्सा

विशेषज्ञ, माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट और एंटमोलॉजिस्ट, आपातकालीन दवाएं, सैनटरी नैपकिन, क्लोरीन की गोलियां, डॉक्सीसाइक्लीन–को लैक्टोपाइरोसिस के बढ़ते मामले में देखते हुए उपलब्ध कराया गया।

अब केरल प्रारंभिक बचाव तथा राहत के काम से आगे बढ़ गया है, तो जरूरतें बदल गई हैं। जितनी जल्दी राज्य में अनिवार्य सेवाएं बहाल होंगी, केरल अपने आप को दोबारा खड़ा करेगा, उतनी जलदी लोग अपनी पूर्व–स्थिति को पुनर्बहाल कर सकेंगे। यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम सब को मिलकर इस अवसर पर प्रयास करना चाहिए ताकि केरल और बेहतर स्थिति में वापिस आए और भविष्य में इस तरह की बाढ़ों से नुकसानों के जोखिम से बचा जा सके। •

राहत एवं बचाव उपाय

- बीमा कम्पनियों को सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत प्रभावित परिवारों/लाभान्वितों को क्षतिपूर्ती आंकलनों और समय पर उसको जारी किए जाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया।
- कृषकों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत शीघ्र क्लीयरेंस हेतु निर्देश जारी किए गए।
- प्राथमिकता पर क्षतिग्रस्त राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।
- विद्युत लाइनों की पुनर्बहाली में राज्य सरकार की मदद करने के लिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) की मदद ली गई।
- 600 करोड़ रुपए की अंतरिम वित्तीस सहायता (प्रधानमंत्री द्वारा 500 करोड़ रुपए और गृहमंत्री द्वारा 100 करोड़ रुपए)
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोश (पीएमएनआरएफ) से मृत्कों के निकटतक रिश्तेदार को 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए के हिसाब से एक अनुग्रह राशि की सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव वालो के लिए प्राथमिकता पर क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों का निर्माणै
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आवास रोजगार योजना (एमएनआरईजीएस) के अंतर्गत श्रम बजट 2018–19 में अतिरिक्त 5.5 करोड़ श्रम दिवसों की स्वीकृति दी गई।
- ठोस तथा बचाव अभियानों के लिए निम्नलिखित तैनाती की गई

  ✓ एनडीआरएफ की 58 टीमें (लगभग 1300 कार्मिक) और 435 नॉवें

  ✓ सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) तथा त्वरित कार्यबल (आरएएफ) की पांच कम्पनियां

  ✓ थलसेना, वायुसेना, नौसेना तथा तट रक्षक – कुल 38 हैलीकॉप्टर

  ✓ इंजीनियरी कृतिक बल के 10 कॉलम तथा 10 टीमें (790 प्रशिक्षित कार्मिक)

  ✓ संसाधनों को ले जाने के लिए 20 एयरकॉफ्ट

केरल की बाढ़ पर संजय कुमार

इस साल केरल में अप्रत्याशित मानसूनी बारिश के कारण राज्य में पिछले 100 वर्षों की सबसे भयंकरण बाढ़ देखी गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) ने राज्य में 58 टीमों को तैनात किया और इस प्रकार यह एनडीआरएफ का अब तक का सबसे बढ़ा बचाव तथा राहत अभियान बन गया जिसने बाढ़ प्रभावित लोगों को इससे उबरने में अत्यधिक सहायता प्रदान की। श्री संजय कुमार, महानिदेशक, एनडीआरएफ ने केरल में बाढ़ के दौरान अपने जवानों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बातचीत की।

प्रश्न. अभियान के दौरान फोकस वाले क्षेत्र क्या थे ?

उत्तर. जैसे ही मूसलाधार बारिश और परिणामी बाढ़ों की खबरें आनी शुरू हुई, तुरंत एनडीआरएफ ने अपनी टीमें की पूर्व तैनाती और जैसे–जैसे स्थिति खराब होती गई, वैसे–वैसे एनडीआरएफ ने अपनी टीमों की संख्या बढ़ा दी। कुल 58 टीमों को मुख्य रूप से लोगों को बचाने तथा सुरक्षित रूप से बाहर निकालने हेतु 10 जिलों में तैनाती किया गया। एनडीआरएफ ने प्रत्यक्ष रूप से 550 से अधिक लोगों की जाने बचाई तथा लगभग 18,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। हमने बीमार तथा जरूरतमंद पीड़ितों को चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई। हमारे लोगों ने बाढ़ में फसे लोगों को ढूंढने तथा उनके परिवार तथा दोस्तों को उनकी सुरक्षा के बारे में सूचित करने के लिए दिन–रात काम किया।

मूसलाधार बारिश से, मुख्य रूप से मध्य केरल में, भूस्खलन, बिल्डिंग/ढांचे गिरने, पेड़ गिरने आदि की घटनाएं हुई। हमारे जवानों ने इन घटनाओं के कारण उत्पन्न स्थिति को सुधारने के लिए अथक रूप से काम किया।

एक बार बचाव तथा सुरक्षित निकासी चरण पूरा हो गया तो एनडीआरएफ कार्मिकों ने स्थानीय प्रशासन की राहत सामग्री बांटने में तथा अनिवार्य सेवाओं की पुनर्बहाली करने में मदद की ताकि पुनर्वास कार्य जल्द–से–जल्द शुरू हो जाए।

स्थिति बहुत चुनौती पूर्ण थी क्योंकि पूरा राज्य प्रभावित था; तथापि हमारे लोगों के समर्पण तथा निश्चय के साथ, हमने इस चुनौती से निपटा।

बल ने अपनी केरल राज्य में बाढ़ के दौरान और पश्चात की गई इस सेवा के लिए अनेक वर्गों से सराहना प्राप्त की।

प्रश्न. भारत अनेक आपदाओं/खतरों से ग्रस्त रहता है। एनडीएमए टीमों को इलाके की असुरक्षितता रूपरेखा के आधार पर विभिन्न स्थानों पर पूर्व तैनाती दी हुई है। यह पूर्व–तैनाती किस प्रकार सहायता करती है ?

उत्तर. एनडीआरएफ का केरल के त्रिशूर जिले में एक स्थायी क्षेत्रीय मोचन केंद्र है वहां पर मौजूद टीमें केरल में तैनात की जाने वाली पहली टीमें थी। केरल की तेजी से बिगड़ती हुई बाढ़ स्थिति को देखते हुए एक स्टेंड बाई के रूप में, अलग–अलग बटालियनों से अतिरिक्त टीमों को बुलाकर तैनात किया गया। राज्य सरकार के अनुरोध पर हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपूर्ण अभियान सुचारु रूप से प्रबंधित हो, हमने केरल में 58 टीमें तैनात कर दी।

प्रश्न. आप राष्ट्रीय संकटकाल प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) के एक सदस्य थे जिसने स्थिति का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली में लगातार बैठकें की। कृपया इसके द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बताएं ?

उत्तर. एनसीएमसी राज्य के संसाधनों की जरूरतों को समझते हुए केरल सरकार के साथ निरंतर संपर्क बनाई रखी थी जो जीवनरक्षक उपकरण, विशिष्ट संसाधन जैसे गोताखोरों की टीमें, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री आदि की थी; ताकि अनवरत, पर्याप्त तथा समय पर सहायता सुनिश्चित हो सके। समिति ने सभी हितधानकों के बीच तालमेल भी सुनिश्चित किया जिससे संपूर्ण अभियान का सुचारु संचालन संभव हुआ।

प्रश्न. एनडीआरएफ ने अब तक आपदा मोचन के काम में लाखों लोगों को प्रशिक्षण दिया है। कृपया इस क्षमता निर्माण पहल के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में कुछ बताएं ?

उत्तर. प्रभावित समुदाय स्वयं किसी आपतकालीन स्थिति में प्रथम मोचक होता है। आपदा के जोखिमों को कम करने में समुदाय का शामिल होना समान रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी जागरुकता तथा सुरक्षा उपायों का अनुपालन आपदा जोखिमों को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि हमारे लोगों की क्षमता का निर्माण हो। इसके अलावा सरकारी मशीनरी की क्षमता को भी बढ़ाने की जरूरत है।

राज्य सरकारों के साथ सहयोग से एनडीआरएफ ने मोचन की कारगर दूसरी लाइन के रूप में राज्य आपदा मोचन बलों को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इन कार्यकलापों की सहायता के लिए, एनडीआरएफ अन्य एजेंसियों जैसे पुलिस, होम–गार्ड, अग्निशमन सेवाएं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, यूथ विंग आदि को प्रथम मोचकों के रूप में कार्य करने के लिए भी प्रशिक्षण देता है।

समुदाय स्तर पर हम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। इन कार्यक्रमों को उनकी भौगोलिक स्थितियों की असुरक्षितता तथा जोखिम कारकों के अनुसार डिजाइन किया गया है। एनडीआरएफ स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाता है। स्कूली बच्चे जोश से भरपूर होते हैं, जल्दी सीखते हैं, कवायदों का अभ्यास करते हैं और अपने परिवारों, पड़ोस तथा समुदायों में परिवर्तन के वाहक (एजेंट) के रूप में भी कार्य करते हैं।

एनडीआरएफ अलग–अलग आपदाओं पर कृत्रिम अभ्यासें का संचालन करता है। ये अभ्यास भागीदार एजेंसियों की जरूरत के हिसाब से भी बनाए जाते हैं उदाहरण के लिए किसी मैनुफेक्चरिंग प्लांट में अग्निसुरक्षा तथा रासायनिक रिसाव पर एक अभ्यास।

इसके अलावा, एनडीआरएफ अपने उपकरण, क्षमता तथा मोबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए भी लगातार काम करता है ताकि आपदा में यह लोगों तक तेजी से पहुंच सके, और लोगों की जान बचाने और आर्थिक हानियों को कम कर सकने में मदद कर सकें। यह बल नियमित रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परिचय अभ्यास (फेमिलीराइजेशन एक्सरसाइजेज) और रिसोर्स मैपिंग करता है ताकि किसी आपातस्थिति के मामले में सुचारु अभियान सुनिश्चित हो जाएं।

प्रश्न. लोगों को आपदा से निपटने की ताकत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए ?

उत्तर. जागरूकता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। लोगों को आपदा जोखिमों के प्रति स्वयं को जागरूक बनाना चाहिए और तदनुसार किसी अप्रिय घटना/आपातस्थिति से निपटने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। हम सबको एक आपदा समुत्थानशील समाज को बनाने के लिए मिल–जुल कर काम करना चाहिए।

अंग्रेजी में रूपांतरित (मूल साक्षात्कार ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग को हिंदी में दिया गया है।) •

बाढ़ से सुरक्षा

संक्रमित भोजन का उपयोग न करें

संक्रमित जल का उपयोग न करें

पानी को उबाल कर पीएं

ताजा भोजन/ शुष्क खाद्य सामग्री उपयोग करें

हाथ धाने के लिए साबुन का नियमित उपयोग करें

साफ–सफाई रखें

मच्छर दानी/मच्छर भगाने वाली दवा का उपयोग करें

कूड़े का उचित निपटान करें

बच्चों/पालतू जानवरों को बाढ़ के पानी के पास अकेला न छोड़ें

उचित जूते–चप्पलों का उपयोग करें

पानी को इकट्ठा न होने दें

टूटी पड़ी तारों, खुली हुई बिजली की तारों आदि से दूर रहें।

कीटाणूनाशकों का उपयोग करें

पता :
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), एनडीएमए भवन
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव, नई दिल्ली–110029.
दूरभाष संख्या :+91–11–26701700
नियंत्रण कक्ष : +91–11–26701728
हेल्पलाइन संख्या : 011–1078
फैक्स : +91–11–26701729

controlroom@ndma.gov.in apdasamvaad@gmail.com/NDMA.in@ndmaindia